









**अमेरिका से बिंगड़ते संबंध**

आवश्यक है कि विदेश नात मत किसा पारवतन से पहल उसके सभी आयामों पर गंभीरता से विचार हो। सिर्फ अमेरिका को सख्ती का संकेत देने के लिए अथवा जज्बाती प्रतिक्रिया में ऐसा करना भारत के हित में नहीं होगा। अमेरिका से बिंगड़ते संबंधों के साथ भारत में अचानक चीन से रिश्ते सुधारने और रूस से संबंध और गहरा करने की ज़रूरत पर अधिक जोर दिया जाने लगा है। संकेत है कि भारत सरकार ने इससे संबंधित प्रक्रियाओं को तेज कर दिया है। उधर, ऐसा लगता है कि चीन ने इस नई परिस्थिति में अपने लिए अवसर देखा है। भारत और अमेरिका के बीच दरार चौड़ी हो जाए, तो चीन के लिए यह अच्छी स्थिति होगी। यह अमेरिका की चीन को धेरने की रणनीति के लिए एक झटका होगा, जिसे स्वरूप देने में गुजरे डेढ़ दशक में अमेरिका ने अपनी काफी ऊर्जा लगाई है। तो खबर है कि चीन ने भारत को उर्वरकों के नियर्था रोकने की नीति में डिलाई दे दी है और कथित रूप डॉपिंग के मामले में भारत के खिलाफ जांच रोक दी है। इधर भारत ने दोनों देशों के बीच सीधी विमान सेवा शुरू करने का ठोस संकेत दिया है। इसी बीच खबर आई है कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी 18 अगस्त को भारत आएंगे। वांग सीमा विवाद पर वार्ता के लिए चीन के विशेष प्रतिनिधि भी हैं। नई दिल्ली में भारत के विशेष प्रतिनिधि अजित डोवल से उनकी बातचीत होगी। साथ ही एलान हुआ है कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर 21 अगस्त को मारको जाएंगे। ये तमाम कूटनीतिक गतिविधियां शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तय चीन यात्रा से पहले हो रही हैं। रूस और चीन दोनों भारत के साथ अपनी त्रिपक्षीय वार्ता का क्रम फिर शुरू करने पर जोर दे रहे हैं। इसलिए ताजा गतिविधियों को उस प्रयास से जोड़ कर देखा जा रहा है। भारत इसके लिए तैयार होता है या नहीं, यह देखने की बात होगी। ऐसा हुआ, तो वह भारत की विदेश नीति में बड़े परिवर्तन का संकेत होगा? स्पष्टतः उसके दूरागमी परिणाम होंगे। इसलिए आवश्यक है कि ऐसे किसी परिवर्तन से पहले उसके सभी आयामों पर गंभीरता से विचार किया जाए। सिर्फ अमेरिका को सख्ती का संकेत देने के लिए अथवा जज्बाती प्रतिक्रिया के तहत ऐसा करना भारत के हित में नहीं होगा।

# भारतीय अर्थव्यवस्था में भरोसे की बड़ी छलांग

डॉ. मयक चतुर्वदा

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की अर्थिक ताकत और नीतिगत प्रतिबद्धता को मान्यता देने वाला एक विशेष समय सामने आया है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी 'एसएंडपी ग्लोबल' ने 18 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भारत की दीर्घकालिक सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को 'बीबीबी-' से बढ़ाकर 'बीबीबी' और अल्पकालिक रेटिंग को 'ए-3' से 'ए-2' कर दिया है। यह सुधार किसी सामान्य तकनीकी घोषणा भर का मामला नहीं है बल्कि यह उस आर्थिक आत्मविश्वास और नीतिगत स्थिरता का प्रमाण है, जिसे भारत ने निरंतर बनाए रखा है। दरअसल, वर्ष 2007 के बाद यह पहली बार है जब भारत की रेटिंग में सुधार हुआ है और इस अंतराल में दुनिया की अर्थव्यवस्था ने कई गहरे झटके झेल हैं। 2008 की वैश्विक वित्तीय मंदी, यूरोपीय क्रांति संकट, काविड महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध और हालिया परिचम एशियाई अस्थिरता जैसी चुनौतियाँ भारत के सामने भी थीं, लेकिन इन सबके बीच भारत ने न केवल अपने विकास को स्थिर बनाए रखा बल्कि भविष्य की संभावनाओं को भी और मजबूत किया। रेटिंग सुधार इसीलिए भारत की नीतिगत क्षमता और आर्थिक लचीलापन दोनों की अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति है।

बना हुआ है निवेशकों का भरोसा-

यह सुधार निवेशकों के लिए एक भारोसे का संदेश है। 'बीबीबी' श्रेणी को निवेश ग्रेड माना जाता है और इसका अर्थ यह है कि भारत अपने वित्तीय दायित्वों को समय पर पूरा करने की पर्याप्त क्षमता रखता है। यद्यपि यह रेटिंग अभी 'ए' या 'एसए' स्तर तक नहीं पहुँची है, लेकिन यह मान्यता महत्वपूर्ण है कि भारत अब उन देशों की श्रेणी में शामिल है जिन्हें सुरक्षित निवेश गंतव्य माना जाता है। अल्पकालिक 'ए-2' रेटिंग भी यही बताती है कि भारत की तकालीन वित्तीय प्रतिबद्धताओं

पर काइ खतरा नहा हा। यह सुधार भारत का उस दीर्घकालिक अर्थिक योजना का हिस्सा है, जिसमें तेज जीडीपी वृद्धि, मजबूत मौद्रिक ढाँचा, नियंत्रित मुद्रास्पर्धा और बुनियादी ढाँचे में भारी निवेश शामिल है। अगर हालिया आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर और स्पष्ट हो जाती है। वित्त वर्ष 2022 से 2024 के बीच भारत की औसत वास्तविक जीडीपी वृद्धि 8.8 प्रतिशत रही है, जो एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सबसे अधिक है। एसएंडपी का अनुमान है कि अगले तीन वर्षों में भी भारत 6.8 प्रतिशत की दर से बढ़ता रहेगा। यह दर उस समय में उल्लेखनीय है जब चीन की वृद्धि दर पाँच प्रतिशत से नीचे जा रही है और यूरोप व अमेरिका की बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ मंदी के दबाव से ज़दा रही हैं। इसका अर्थ यह है कि भारत वैश्विक विकास का प्रमुख इंजन बन चुका है और आने वाले वर्षों में इसका दबदबा और बढ़ेगा।

राजकोषीय घाटे का कम होना लेकर आया है नई उम्मीद- इस वृद्धि के पीछे सरकार का राजकोषीय प्रबंधन और बुनियादी ढाँचे पर केंद्रीय नीतियां प्रमुख कारण रही हैं। महामारी के दौरान भारत का राजकोषीय घाटा जीडीपी के 9 से 13 प्रतिशत तक पहुँच गया था। लेकिन अब यह घटकर वित्त वर्ष 2025 में 4.8 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2026 में 4.4 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य है। राज्य सरकारों का घाटा भी अगले तीन-चार वर्षों में औसतन 2.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। केंद्र और राज्यों दोनों को मिलाकर सामान्य सरकारी घाटा 2029 तक 6.6 प्रतिशत पर आ सकता है। यह सुधार न केवल वित्तीय अनुशासन का प्रमाण है बल्कि यह भी बताता है कि सरकार ने बड़े पैमाने पर निवेश को बिना चालू खाता घाटा बढ़ाए सफलतापूर्वक वित्तपोषित किया है। यह भारत की विश्वसनीयता में बढ़ोत्तरी करने वाला कारक है।

बुनियादी ढाँचे पर फोकस ने विकास की गति को कई गुना बढ़ा दिया- बुनियादी



दाँचे के क्षेत्र में किए गए निवेश ने भी भारत की आर्थिक संभावनाओं को एक नई दिशा दी है। वित्त वर्ष 2026 तक केंद्र सरकार का पूँजीगत व्यय 11.2 ट्रिलियन रुपये तक पहुँचन का अनुमान है, जो जीडीपी का 3.1 प्रतिशत होगा। यदि राज्यों को मिलाया जाए तो यह अनुपात 5.5 प्रतिशत तक जाता है। इतनी बड़ी पूँजीगत हिस्सेदारी के बल आँकड़ों का खेल नहीं है बल्कि यह सड़कों, रेलमार्गों, बंदरगाहों, ऊर्जा संयंत्रों और डिजिटल अवसरणों के निर्माण में परिलक्षित होती है। यह निवेश दीर्घकालिक विकास की बाधाओं को दूर करने में सहायक है। भारत की समस्या लंबे समय तक यही रही कि यहाँ बुनियादी ढाँचे की कमी विकास की गति को रोक देती थी। अब केंद्र की मोदी सरकार इस कमी को व्यवस्थित रूप से दूर कर रही है और इसका लाभ उद्योग, व्यापार और नागरिकों सभी को मिलेगा। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण और मौद्रिक नीति की स्थिरता इस रेटिंग सुधार के दूसरे बड़े कारण हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2015 से मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का ढाँचा अपनाया, जिसमें 2 से 6 प्रतिशत के बीच खुदरा मुद्रास्फीति रखने का लक्ष्य है। पिछले तीन वर्षों में औसतन मुद्रास्फीति 5.5

प्रतिशत पर रही है और हाल के महीनों में यह घटकर 2 प्रतिशत के करीब आ गई है। जुलाई 2025 में मुख्य सीपीआई मुद्रास्फीति केवल 1.6 प्रतिशत रही, जो वैश्विक ऊर्जा मूल्य अस्थिरता के बावजूद उल्लेखनीय है। यहीं कारण है कि फटवरी 2025 में जिर्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर को घटाकर 5.5 प्रतिशत कर दिया। मुद्रास्फीति नियंत्रण का यह अनुभव निवेशकों को भरोसा देता है कि भारत में मूल्य अस्थिरता आर्थिक विकास की राह में बाधा नहीं बनेगी।

रेटिंग सुधार से अंतरराष्ट्रीय बाजार से सुविधाएं मिलना तय- विदेशी निवेशकों के लिए भारत अब और अधिक आकर्षक बन गया है। रेटिंग सुधार का सीधा अर्थ है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार से भारत को सस्ता ऋण मिलेगा। इससे न केवल सार्वजनिक परियोजनाओं की फंडिंग आसान होगी बल्कि निजी क्षेत्र को भी अधिक अवसर मिलेंगे। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और पोर्टफोलियो निवेश दोनों में वृद्धि की संभावना है। निवेशकों की नजर में स्थिर नीतियाँ और भरोसेमंद संस्थागत ढाँचा सबसे बड़ा आकर्षण होता है। भारत ने इस दिशा में उल्लेखनीय प्राप्ति की है, चाहे दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता हो, है। इस पूरे परिदृश्य में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि क्या भारत इस अवसर का दीर्घकालिक सुधारों को आगे बढ़ाने पाएगा? रेटिंग सुधार केवल एक अंत नहीं। इसे बनाए रखने और आगे के लिए भारत को राजकोषीय अनुशासन और मजबूत करना होगा, नियंत्रित विविध करना होगा, हरित ऊर्जा और तकनीकी को बढ़ावा देना होगा तथा सामाजिक निवेश बढ़ावा होगा। विकास तभी टिक सार्थक होगा जब वह समाज के हर पहुँचे। अतः यह कहना अतिशयोक्ति न कि एसएंडपी का रेटिंग सुधार भारत भरोसे का एक प्रमाण-पत्र है। यह प्रमाण केवल भारत सरकार के आर्थिक प्रबंधी नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र की ओर भारतीय समाज के लीचीलापन का यह अवसर है कि हम इस विश्वास न गहरा करें और आने वाले वर्षों में भैंसी ऐसी स्थिति में पहुँचाएँ, जहाँ उसकी रेटिंग ऊपर जाए और वह दुनिया की सबसे अमेरिका और शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं जाए। कहाना होगा कि इस भरोसे के रखना ही अब भारत की सबसे बड़ी और सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए।

# गुलामी में भारत की हथकरघा उद्योग को नुकसान

सजय गारस्वामा

भारत के गुलामी के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत की हथकरघा संस्कृति को पूँजीपति के द्वारा कैसे नष्ट किया गया, इसके बारे में जानना आवश्यक है पुराने हस्तशिल्पों का हास भारत के अर्थिक संक्रमण की सर्वाधिक नाटकीय घटना है। भारत में हस्तशिल्प उद्योग सदियों से फलता-फूलता आ रहा था। सत्रहवीं और अठाहवीं शताब्दी के आरंभ में भारत में निर्मित वस्तुएं विश्व प्रसिद्ध थीं। प्राचीनकाल से ही मिश्र वासियों, ईरानियों, चीनियों, यूनानियों, रोमनों, अरबों और यूरोपियनों ने भारत के साथ हस्तशिल्प में बने वस्तुओं के लिए व्यापारिक सम्बन्ध रखे। भारतीय हस्तशिल्प उत्पाद इन देशों में प्रशंसा और ईर्ष्या का कारण बना रहा। युगों तक इसके कारण भारत को “शानदार भारत” कहा गया। परन्तु भारत में जैसे-जैसे अंग्रेजों की राजनीतिक सत्ता में बढ़ोत्तरी हुई और जब उन्होंने भारत के आधिक जीवन में हस्तक्षेप करने शुरू किए, भारत के हस्तशिल्प उद्योगों का बड़ा ही आकस्मिक एवं सर्वग्राही विवर्ण होने लगा। भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों में हास के यद्यपि अनेक कारण रहे, परन्तु इसके कई कारण कतिपय रूप से महत्वपूर्ण

हा। जस इंग्लॅड मे औद्योगिक क्रात के फलस्वरूप अंग्रेजों द्वारा भारत पर अपने औद्योगिक अर्थव्यवस्था को लादना, भारत में पुराने देशी दरबारों के संरक्षण का लोप, मशीन उद्योगों की शुरूआत, विदेशी शासन की भारत में स्थापना और उसका राजनीतिक दबाव, बिट्रेन की आर्थिक नीति जिसके तहत उसने भारत को मूल रूप से कृषि प्रधान बनाए रखने की कोशिश की, 1813 ई. का चार्टर एक इत्यादि। अर्धशास्त्र का एक आधारभूत सिद्धांत है कि सहज श्रम से या औद्योगिक तकनीकों से वस्तुओं के उत्पादन में अपेक्षाकृत कम खर्च होता है। इस तरह मशीन उद्योगों के द्वारा कम समय में अधिक और सस्ते मालों की बिक्री प्रारंभ हुई, जिससे हस्तशिल्प से निर्मित वस्तुओं की मांग तथा बिक्री में कमी आई। मशीनीकरण से नुकसान रूप हस्तशिल्प का विनाश अंग्रेजी सत्ता के राजनीतिक दबाव व विदेशी मशीन उद्योगों के सस्ते उत्पादनों के कारण हुआ। इसके परिणामस्वरूप हस्तशिल्प उद्योगों के कारीगरों की जीविका का साधन नष्ट हो गया। यद्यपि 1850 ई. के पश्चात भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना भी हुई, परन्तु इतनी तेजी से नहीं कि बराजगारी और बर्बादी के कागर पर पहुंच करागारा और दस्तकारी को पूर्ण रोजगार मिल जाए। भारतीय हस्तशिल्पी अपने द्वारा निर्मित उत्कृष्ट वस्तुओं को विदेश भेजने थे तो वहाँ भी केवल अभिजात और कुलीन वर्ग के लोग ही साथारणतः उसे खरीद पाते थे। इस प्रकार व सीमित मंडी तब और भी सीमित ह गई जब भारतीय वस्तुओं के प्राप्ति विदेश में अवरोधक कानून बना जाने लगे। इसका भारतीय दस्तकारी व हस्तशिल्प पर बुरा प्रभाव पड़ा रोजमरा की आवश्यकताओं व उत्पादन भारतीय हस्तशिल्प दस्तकारी उत्पादन के विकास व लिए आवश्यक था, लेकिन इ प्राथमिकता नहीं मिली। बिट्रेन तथा अन्य देशों में मशीन से निर्मित सस्ते वस्तुओं की बाढ़ भारत के ग्रामीण इलाकों में हस्तशिल्प के पतन व मूल कारण था। रेलवे तथा परिवहन के अन्य साधनों के विकास से इ बाढ़ को फैलने में मदद मिल्या। क्योंकि अब ग्रामीण लोगों व पहुंच भी विदेशों में उत्पादित सस्ते वस्तुओं तक होने लगी। कारखाने में विकसित उत्पादन की सस्ती और लाभकारी तकनीक का मुकाबल रूप हस्तशिल्प व दस्तकारी न कर सकते और प्रायः नष्ट हो गई। औद्योगिक क्रांति का दौरा रूप इंडेंड में औद्योगिक

क्रात क पारणाम्बरूप भारतीय हस्तशिल्प व दस्तकारी उद्योगों का जम कर विनाश हुआ। ईंस्ट इंडिया कम्पनी ने इंग्लैंड के उत्पादन को भारत में खपाने का प्रयास किया। 1813 ई. के कम्पनी चार्टर एक्ट के द्वारा जब भारत में कम्पनी के व्यापारिक एकाधिकार को लगभग समाप्त कर दिया गया तो भारतीय बाजारों में सस्ते दर की अच्छे किस्म की वस्तुओं की बाड़ आ गई इससे भारतीय हस्तशिल्प व दस्तकारी उद्योगें द्वारा बनाई गई वस्तुओं की बिक्री में भारी कमी आई। पूँजी की कमी, तकनीकी ज्ञान के अभाव आदि के कारणों से भारत औद्योगिकरण का लाभ न उठा सका और अधिक रूप से पिछड़ गया। ग्रामीण उत्पादन प्रणाली में मशीन का प्रयोग बढ़ने से भी हस्तशिल्प उद्योगों का हास हुआ, मशीनों द्वारा स्वाभाविक रूप से बढ़ती मांग को पूरा किया जाने लगा। देशी रजवाड़े हस्तशिल्प उद्योगों के संरक्षक थे। उनके संरक्षण के समाप्त होने के कारण हस्तशिल्प में उत्पादित वस्तुओं के खरीदार समाप्त हो गए, जिसका दस्तकारी व हस्तशिल्प पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा। ईंस्ट इंडिया कम्पनी यद्यपि इन उद्योगों को प्रश्रय प्रदान कर सकती थी, परन्तु उसने अपने गृह राज्य के

म आ कर एसा काम क्या भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के अहितकर हुए। हस्तशिल्प व नारी उद्योगों का इसलिए भी यहा हुआ कि अंग्रेजों की सीमा नैति और परिवहन नियमन द्वारा भारत के हित के प्रतिकूल जिससे भारतीय व्यापारियों को र करने में अनेक कठिनाईयों का करना पड़ा। उदाहरण स्वरूप लिंटन के शासनकाल में भारती कापास की वस्तुएं जो बाहर रों में भेजी जाती थी, उन पर रक्त शुल्क लगाया गया, जबकि में इंग्लैंड से तार्ह कई कापास वस्तुओं पर इस शुल्क को माफ दिया गया। इसके परिणामस्वरूप वस्तुओं के मूल्य में बढ़ जबकि इंग्लैंड में बनी वस्तुओं ल्य में कमी। इससे भारतीय ओं की मांग पर काफी बुरा प्रभाव जिससे हस्तशिल्प उद्योग भी चर द्वारा। भारतीय हस्तशिल्प दस्तकारी उद्योगों के हास का कारण इनके मंडी या बाजार का त होना भी रहा, चूंकि भारत के शिल्प उद्योग मध्ययुगीन समाज मित अभिजात्य वर्ग की पहुँच त्री सीमित थे। लिंटन की आर्थिक के कारण भी परम्परागत शालप व दस्तकारी उद्योगों का

नाश हुआ। इस नात के तहत भारत में नये उद्योगों को विकसित करने से रोका गया। क्योंकि भारत में ये उद्योगों के विकास से ब्रिटेन में पादित वस्तुओं की भारत में खपत घट जाती। इसके अलावे एक अन्य विवरण से भी ब्रिटेन ने भारत को नतः कृषि प्रधान बनाए रखने का वापस किया। चौकी इंस्लैंड को अपने उद्योगों को चलाने के लिए भारतीय चेंचे मालों के उत्पाद की जरूरत पड़ी। इस तरह भारत एक औद्योगिक द्रूढ़ का कृषि प्रधान औपनिवेशिक उद्योग बन कर रह गया। महात्मा गांधी ने कभी कहा था, “सिफ्ट यह हन्ता ही काफी नहीं है कि हस्तकरवा न एसा उद्योग है जिसे पुनर्जीवित करने जाने की आवश्यकता है।” लेकिं सबसे बड़ी आवश्यकता यह बात पर जोर देने की है कि यह सारा केंद्रीय उद्योग है और अगर हमें पनी ग्रामीण संस्कृति को वापस ले ते हुए दोबारा स्थापित करना चाहते हों तो हमें इस ओर भी ध्यान देना चाहिए।” चाहे वह कलाकारी हो, बुनाई न कवाशी हो या फिर निर्माण और इकूलिंगीरी हो, जिन लोगों ने इहैं तैयार करने में अपना अधिकतर समय लगाताया होता है वही इस काम से लाने वाली संस्थाएं को बेहतर तरीके जान सकते हैं।

# एनसीईआरटी ने विभाजन पर किया सत्य का संधान

डॉ. मयंक चतुर्वेदी

A photograph showing four men seated at a table. From left to right: a man in a white turban and light-colored vest; a man in a dark suit; a man in a dark suit and tie; and a man in a light-colored suit. Behind them is a large circular logo for NCERT, featuring a stylized design inside a circle with the acronym "NCERT" below it.

यही असंतोष आगे चलकर कटुता में बदल गया, जिसके बाद जिन्होंने मुस्लिम लीग को एक अलग ताकत के रूप में खड़ा किया। 1940 का नाहार प्रस्ताव इस दिशा में निर्णयक तोड़ था, जब मुस्लिम लीग ने पहली बार औपचारिक रूप से पाकिस्तान की मांग रखी। इसके बाद जिन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे' जैसे हिंसक आंदोलनों का सहारा लिया, जिनके परिणामस्वरूप हजारों लोग मारे गए। जिन्होंने का तर्क था कि मुसलमानों की राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान हेंडुओं से बिल्कुल भिन्न है और वे एक ही राष्ट्र में रहकर सुरक्षित नहीं रह सकते। यह विचारधारा मूलतः वेभाजनकारी थी, जिसने भारत के सांस्कृतिक आधार देना ऐसे कांग्रेस वे भी उतनी का यह प्रलगातार आंदोलन एक रण आंदोलन उदाहरण चेतावनी व की नींव उस समय ने तेज़तः क पर पहुँचे

बढ़ना संभव नहीं है। पटेल ने कई बार यह कहा कि यदि विभाजन से देश की आजादी शीघ्र आ सकती है तो इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। नेहरू भी सत्ता हस्तांतरण में जल्दबाजी के पश्चात् थे। लोहिया जैसे समाजवादी चिंतकों ने उस समय ही यह कह दिया था कि कांग्रेस ने पाकिस्तान को 'एक मजबूरी नहीं बल्कि अपनी सुविधा के लिए स्वीकार किया'। इस तरह कांग्रेस की राजनीतिक सोच और सत्ता प्राप्ति के उत्तावले पन ने विभाजन को और तेज़ कर दिया। इसके अलावा एक तीसरा पक्ष भी है, ब्रिटिश सत्ता की भूमिका, यहां इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन अर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत कमज़ोर हो चुका था और वह भारत को जल्द से जल्द छोड़ना चाहता था। बावेल जैसे गवर्नर जनरल अखंड भारत के पक्ष में थे, लेकिन 1947 में जब एटली की लेवर सम्पर्क ने सत्ता माउंटबेटन को सौंपी, तो परिदृश्य पूरी तरह बदल गया। माउंटबेटन ने जनबूझकर सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को जल्दबाजी में पूरा किया। उन्होंने सीमाओं के निर्धारण का जिम्मा सर रेडिकलफ जैसे व्यक्ति को सौंपा, जिन्हें भारत के भूगोल और समाज की कोई गहरी

ज्ञान नहीं थी। नतों यह हुआ कि पाएँ खींचने का काम बिना स्थानीय तत्विकाताओं की परवाह किए दबावाजी में हुआ और पंजाब तथा लल जैसे प्रदेशों से हिस्सों में बैंकर काम की ज़ज़ाला में झोंक दिए गए। अंटबेटन के इस रवैये की आलोचना ज भी इतिहासकार करते हैं कि यह द्वारा धैर्य रखा जाता तो इतनी भयावह को टाला जा सकता था। कांग्रेस और अन्य दलों की वैचारिक कमज़ोरी भी इस प्रक्रिया में सामने आई। जिन्होंने तभी अलगाववाद की खुलकर दी की और अपनी मांग को कठोरता रखा। इसके विपरीत कांग्रेस नेताओं द्वारा चुनौती का वैचारिक स्तर पर बनाना करने के बजाय समझौतों और विवादों का रस्ता अपनाया। इस्लामी नीति के मूल चरित्र मजहबी इवाद और अलगाववाद को कभी राहि से चुनौती नहीं दी गई। इसके बाय अंग्रेजों को दोषी ठहराकर इस्या से बचने की कोशिश की गई। इसे मुस्लिम लोग का मनोबल बढ़ाता नहीं और कांग्रेस बार-बार पछे हटती दिलचस्प बात यह है कि मौताना तुलना कलाम आजाद जैसे नेता, होने खुद को राष्ट्रवादी घोषित ने का प्रयास किया, वह भी मूलतः इस्लामी चिंतन से प्रेरित थे।

**बिजनेस के क्षेत्र में आपको बड़ा धन लाभ होगा और शत्रु पक्ष आज आपसे दूरीयां बनाकर रहेंगे।** आज आपको फर्नीचर के बिजनेस में बढ़िया लाभ होगा और आपको बड़े प्रोजेक्ट का आर्डर भी मिलेगा। राइटर आज कोई नई स्टोरी लिख सकते हैं जिसे लोगों द्वारा खूब पसंद किया जायेगा।

**वृश्चिक राशि:** आज का दिन आपके अनुकूल रहने वाला है। आज अगर किसी बिजनेस ट्रिप के लिये आप बाहर जा रहे हैं, तो घर के बड़े-बुजुर्ग का आशीर्वाद लेकर जाएं। आपका काम सफल होगा। आज आपके जीवनसाथी को तरकी का अच्छा अवसर मिलेगा। आज आपको नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, जो आपके करियर को आगे लेकर जायेंगे।

**धनु राशि:** आज आपका दिन पहले की अपेक्षा अच्छा रहेगा। आज आप परिवार वालों के साथ क्वालिटी टाइम स्पैंड करेंगे साथ ही जीवनसाथी के साथ आपकी लंबी बातचीत हो सकती है, इससे आपके रिश्ते बेहतर होंगे। आज आप दोस्तों के साथ थियेटर में मूँही देखने की प्लानिंग कर सकते हैं। आज किसी खास काम में आपको सफलता मिलेगी साथ ही साथ आपके मन में नए-नए विचार आ सकते हैं।

**मकर राशि:** आज का दिन आपके लिए मिला-जुला रहेगा। आज एकाग्र मन से किया गया काम लाभदायक साबित होगा। आज किसी जिम्मेदारी को अनदेखा करने से आपको बचना चाहिए और जल्द से जल्द उसे पूरा करना चाहिए। आज आपकी सेहत ठीक-ठाक रहेगी, जिससे आप कम से कम समय में काम निपटाने की कोशिश करेंगे।

**कुम्भ राशि:** आज आपका दिन उत्तम रहने वाला है। आज आप किसी बिजनेस की शुरुआत अपने दोस्त के साथ मिलकर कर सकते हैं। आज आप दोस्तों की बथ्डे पार्टी में जायेंगे जहां बाकी दोस्तों के साथ इंज्वाय करने का मौका मिलेगा। आज आप नई स्किल सीख सकते हैं जिसका लाभ आपको भविष्य में जरूर मिलेगा।

**मीन राशि:** आज आप का दिन नई उमंग के साथ शुरू होने वाला है। आज आपका अच्छा व्यवहार सोसाइटी में अलग पहचान बनाने में मदद करेगा। कॉटेक्टर के लिए आज का दिन धनलाभ देने वाला, आज आपको बड़ा कॉन्फ्रैट क्लियर मिल सकता है। आज आप मौसमी फलों का सेवन करें, जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा।





## Heavy rains in the mountains cause floods in the plains, IMD issues red alert

**New Delhi,** Heavy rains in Himachal Pradesh and Uttarakhand have created flood-like conditions in many states including Punjab, Haryana and Delhi. People in low-lying areas of Delhi have been alerted due to the rising water level of Yamuna. The Indian Meteorological Department (IMD) on Monday issued a red alert for heavy rains in Chhattisgarh, Odisha, Andhra Pradesh, Telangana, Maharashtra, Goa and Karnataka in view of the latest low pressure area. Along with this, clouds will also rain in Mumbai and Delhi. Due to torrential rains in Uttarakhand, a 40-meter walkway connecting the second Kedarnath Mahadev temple collapsed near Bantoli. This trapped 142 passengers, who were rescued by the SDRF with the help of ropes. The Meteorological Department has issued a yellow alert for heavy rains in some places in the state's Pauri, Bageshwar, Pithoragarh and Nainital. On the other hand, the monsoon will weaken a bit in Himachal Pradesh, but there is a yellow alert in Kangra and Chamba



districts. 353 roads are blocked due to landslides in the state. Due to heavy rains in Delhi on Sunday, people had to face trouble due to waterlogging and jams on the roads. The Meteorological Department has also forecast sporadic rains on August 18. A western disturbance and low pressure area is forming, which will also affect Delhi NCR. There will be heavy rains in Mumbai on August 18-19. Apart from Raigad, Ratnagiri, there is a red alert in the Ghats of Pune, Kolhapur and Satara.

The monsoon phase in Uttar Pradesh has gradually started weakening, due to which heat and humidity have started bothering with the rise in temperature. There may be light rain at some places in the state on Monday. In Bihar too, there is a possibility of light to moderate rain with lightning in 17 districts. On the other hand, due to the monsoon trough passing through the west-south part of Madhya Pradesh and the low pressure area becoming active, there is a possibility of heavy rain in 14 districts.

Monsoon has become active again in Rajasthan, due to which good rains occurred in Kota, Udaipur, Sriganganagar, Sirohi and Rajasamand districts on Sunday. On the other hand, the heat and humidity have increased due to the cessation of rain in the eastern parts. The Meteorological Department has issued a yellow alert for rain in 27 districts on August 18. Heavy rains may occur in some parts of Kota and Jaipur divisions along with strong winds at a speed of 30-50 km/h. Due to heavy rains in Jammu and Kashmir, the water level of the Ravi river has increased. Due to this, many posts and border areas of Pathankot in Punjab have been submerged in water. Water has increased by 2-3 feet in some villages. A yellow alert has been issued regarding rain in the state on Monday. Heavy rains may occur here in Pathankot, Gurdaspur, Hoshiarpur and Rupnagar. On the other hand, rain is expected in Panchkula, Yamananagar, Karnal, Panipat, Sonipat, Gurugram and Faridabad in Haryana.

## Threat to bomb 3 schools including DPS in Dwarka, premises evacuated

**New Delhi,** Once again, there has been a threat to bomb schools in Delhi. This time the threatening email has come to 3 schools in Dwarka. Police said that Delhi Public School (DPS), Shriram World School and Modern School have been threatened. Police received information about the threat from the schools at around 7 am. Teams of Delhi Police, bomb disposal squad and dog squad reached the spot and evacuated the premises. Police officials said that they have checked all the schools, but nothing suspicious has been found yet. Children in some schools have



been sent home. Police say that the schools received the threat through email, the sender of the email is being traced. A college has also been reported to have received a threat,

however, it has not been confirmed. The school management has informed the parents of the students. The series of threats to schools and colleges continues in the national capital Delhi. Last year also, more than 200 schools had received threats. Last month in July, 5 schools of Dwarka received threats of bombing and the threatening email also came from the same address. Then St. Thomas School, Delhi International School, Central Academy School, GD Goenka School and Modern International School had received threats.

## Major accident during Krishnashtami procession, 5 died due to electrocution

**Hyderabad,** A tragic accident occurred during a Sri Krishnashtami procession in Hyderabad, the capital of Telangana. A chariot being pulled by devotees came in contact with the overhead power wires. Five people died on the spot and four others were injured in this accident. The incident is being investigated. The incident took place in Gokulnagar under Ramapuram on Sunday night. The deceased have been identified as Krishna Yadav (21), Suresh Yadav (34), Srikanth Reddy (35), Rudravikas (39) and Rajendra Reddy (45). According to police sources, the incident took place in Gokulnagar area when the chariot of a procession being taken out as part of the Krishna



Janmashtami celebrations came in contact with the overhead power wires. The vehicle pulling the chariot was being repaired, when some local youths stopped it on one side and pulled it by hand. During this time the chariot came in contact with the electric wires. At least nine youths pulling the chariot got an electric shock and fell on the ground. This changed the atmosphere of happiness and devotion into screams. Local people and eyewitnesses rushed to the spot and took the unconscious people to the hospital after giving them first aid, where doctors declared five people dead. Four others are being treated in a private hospital. Hearing the news of this death, the entire area was filled with mourning. It is being investigated how this accident happened. People are surprised that how high was the chariot that it came in contact with the wire. It is said that Union Minister Kishan Reddy's gunman Srinivas is also among the injured.

## Supreme Court grants bail to former West Bengal Education Minister Partha Chatterjee

**New Delhi,** The Supreme Court on Monday granted bail to former West Bengal Education Minister Partha Chatterjee in the School Service Commission (SSC) teacher recruitment scam case. A bench of Justices MM Sundareswaran and NK Singh gave this verdict while hearing the bail plea filed by Chatterjee. Chatterjee had challenged the investigation of the Central Bureau of Investigation (CBI) in the 2022 case. Along with him, former Vice Chancellor Subirsh Bhattacharya and officer Shanti Prasad Sinha have also got bail. Trinamool Congress (TMC) leader Chatterjee will not be released even after getting bail from the Supreme Court as the hearing of another CBI case related to the

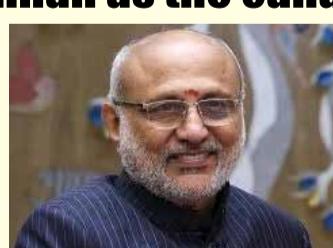


primary teacher recruitment scam is still pending. Earlier, the Supreme Court had granted bail to Chatterjee on December 13, 2024 in the Enforcement Directorate (ED) money laundering case. Chatterjee has 3 ED and 5 CBI cases registered against him. He is accused of scam in the recruitment of Group C and D employees, 9th-10th class assistant teachers and primary teachers. He is expelled from TMC.

## Why did NDA choose CP Radhakrishnan as the candidate for the post of Vice President

### Bet on OBC and South India equation

**New Delhi,** The BJP-led National Democratic Alliance (NDA) on Sunday (August 17) chose Maharashtra Governor CP Radhakrishnan as its candidate for the post of Vice President. Prime Minister Narendra Modi himself approved his name in the BJP Parliamentary Party meeting. After that, BJP National President JP Nadda created a stir in political circles by announcing it. In such a situation, let us know why the NDA has chosen Radhakrishnan. Born on October 20, 1957 in Tirupur, Tamil Nadu, Chandrapuram Ponnuswamy Radhakrishnan has been a senior BJP leader. He is serving as the Governor of Maharashtra from July 31, 2024. Prior to this, he



was the Governor of Jharkhand from February 2023 to July 2024 and also held additional charge of Telangana from March to July 2024. Similarly, he also held additional charge of Lieutenant Governor of Puducherry from March to August 2024. Radhakrishnan started his political career with Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) and Jansangh. He joined RSS and Jansangh as a member in the year 1974 at the age of just 16. He became the secretary of Tamil Nadu BJP in the year 1996 and was elected Lok Sabha MP from Coimbatore in 1998-99. He also held the responsibility of Tamil Nadu BJP President from 2004 to 2007. Similarly, he was in charge of Kerala BJP from 2020-2022. The BJP has chosen Radhakrishnan for the post of Vice President keeping in mind the assembly

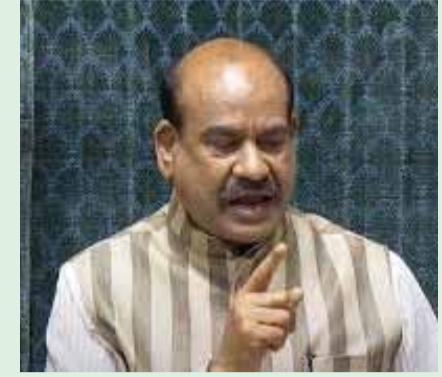
result was that BJP could only get 240 seats in the Lok Sabha elections, which was 32 less than the majority. Now BJP has taken a step to strengthen ties with RSS and send a message to the ideological backbone of the organization. BJP has played a big master stroke by choosing Radhakrishnan. It will not be easy for anyone to oppose him. Radhakrishnan himself is from Tamil Nadu and at present there is a DMK government there. Due to this, now Chief Minister MK Stalin will not be able to oppose the state's candidate even if he wants to, looking at the local political equations. In such a situation, DMK, which is BJP's arch rival in central politics, will now be forced to support Radhakrishnan. After continuous efforts, BJP's position has improved in Tamil Nadu, but it is still not getting the expected support. Now the party

has played the OBC card by putting Radhakrishnan forward. Actually, Radhakrishnan comes from the Gaunti (Kongu Vellalar) community included in OBC. This is an important vote bank in Tamil Nadu politics. In Western Tamil Nadu, OBCs prove to be even more decisive. In such a situation, BJP has played a big gamble. Radhakrishnan is currently the Governor of Maharashtra. There have been cultural and political relations between Maharashtra and Tamil Nadu for a long time. There are a large number of people from the Tamil community in Mumbai and Pune. There is also a decades-old affinity between Tamil Nadu's film industry and Maharashtra's Marathi culture. By choosing Radhakrishnan, BJP has shown that a leader from the South can rule in Western India and hold the number two position in Delhi.

## Do not try to damage government property, Om Birla warned

**New Delhi,** Lok Sabha Speaker

Om Birla on Monday issued a stern warning to opposition MPs protesting against the Special Intensive Revision and other issues, urging them not to damage government property. Addressing the House, Birla said that if you ask questions with the same force with which you are raising slogans, it will be beneficial for the people of the country. He said, the public has not sent you to destroy government property. I request you and warn you that no member has the privilege to destroy government property. He cautioned the MPs that if they continue to do so, they will have to take some decisive decisions. Birla said, if you try to destroy government property, I will have to take some decisive decisions and the people of the country will see you. Action has been taken against members for such incidents in many assemblies. I warn you again do not try to damage government property. This is my request to you. Meanwhile, due to the uproar, the proceedings of the Lok Sabha were adjourned till this afternoon. Earlier today, India Block leaders protested in the Parliament premises against SIR in Bihar. Let us tell you that since the beginning of the monsoon session of Parliament on July 21, opposition parties have been protesting



against the revision of the voter list. The ruling party has accused the opposition of disrupting the proceedings of Parliament. Terming this ongoing process as silent, invisible rigging, India Block leaders waved banners calling for an end to vote theft. A day earlier, Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar addressed a press conference in the national capital and refuted the vote theft claims leveled by Congress MP Rahul Gandhi against the Election Commission of India. He termed the allegations of bias leveled by the Leader of Opposition in the Lok Sabha as an insult to the Constitution of India. Also, the Chief Election Commissioner also asked Congress MP Rahul Gandhi to either submit a signed affidavit or apologize to the country for his remarks.

## Vice Presidential Election: Rajnath Singh spoke to Kharge to ensure unopposed victory for Radhakrishnan

**New Delhi,** Defense Minister Rajnath Singh spoke to Congress President Mallikarjun Kharge on Sunday evening and sought support for National Democratic Alliance (NDA) Vice Presidential candidate CP Radhakrishnan. According to the report, the Vice Presidential election to be held on September 9 will be held under the supervision of Rajnath Singh on behalf of the NDA. Union Minister Kiren Rijiju has been made the election agent. The NDA on Sunday declared Maharashtra Governor CP Radhakrishnan as its candidate for the Vice Presidential election. BJP National President JP Nadda made this announcement after the meeting of the party parliamentary



board in New Delhi. BJP President Nadda said that the party will contact the opposition to ensure consensus and possibly unopposed election. Addressing a conference here, Nadda said, "We will also talk to the opposition. We should also get their support so that together we can ensure unopposed election for the post

of Vice President." He said that the party is trying to garner the consent of the opposition in this direction. NDA has full support in this. CP Radhakrishnan is our NDA candidate for the post of Vice President. Radhakrishnan is currently the Governor of Maharashtra. Senior BJP leader Radhakrishnan was elected to the Lok Sabha twice from Coimbatore and was earlier working as the state president of Tamil Nadu BJP. His political career began with joining organizations like RSS and Jan Sangh and joining student politics. Since then he has used politics as a medium to serve the people. He has worked on national unity, social welfare, and social welfare.

## Preparations to bring impeachment motion against Chief Election Commissioner amid vote theft controversy

**New Delhi,** The opposition's India Alliance is preparing an impeachment motion against Chief Election Commissioner (CEC) Gyanesh Kumar amid the vote theft controversy. Opposition parties are angry with Kumar's answers given in the press conference on Sunday, in which he asked Leader of Opposition Rahul Gandhi to apologize and give an affidavit without naming him. The opposition can also include those parties for the impeachment motion, which are not officially part of the India Alliance. According to sources, apart from India Alliance, the impeachment motion against the Chief Election Commissioner can also get support from Biju Janata Dal (BJD) of Odisha, Bharat Rashtriya Samiti (BRS) of Telangana and YSR Congress Party of Andhra Pradesh as they also complained to the Election Commission about irregularities in the voter list. Opposition parties can bring the impeachment motion in the winter session as the monsoon session is ending on August 21. CEC Kumar on Sunday, without naming the Leader of Opposition in the Lok Sabha Rahul Gandhi, had said at the National Media Center in Delhi on the allegations of vote theft that he will either have to give an affidavit or apologize to the country. There is no third option. He had said that if the affidavit is not received within 7 days, it means that all these allegations are baseless. He also rejected the allegations of double voting.

## Supreme Court expressed concern over the condition of cadets who became disabled during training

**New Delhi,** The Supreme Court has taken suo motu cognizance of the difficulties of those cadets who were discharged on medical grounds midway due to injury or disability during training. The Supreme Court has sought a response from the Central Government and the Defense Forces and said that the arrangement of insurance covers should be considered to provide financial security to such cadets. A bench of Justices BV Nagarathna and R Mahadevan heard the case. The court has scheduled the next hearing of the case for September 4. The bench asked Additional Solicitor General Aishwarya Bhati, appearing for the Center, to seek instructions regarding increasing the ex-gratia amount of Rs 40,000 given for medical expenses to the cadets who became disabled during the training program. The apex court asked the Center to consider a plan for rehabilitation of these disabled candidates after their treatment to bring them back to desk jobs or any other work related to defense services. The bench said, we want the brave cadets to remain in the army.